नगर निगम चुनाव

एक और रबड़-स्टंप

बराये नाम प्रजातंत्र में सत्ता तंत्र का नंगा नाच

हरियाणा के सबसे अहम शहर फरीदाबाद में निगम चुनाव कई मायनों में प्रजातंत्र का एक खुल्लमखुल्ला और भोंडा मजाक बन कर रह गया है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी इसे सत्ता की अंदरूनी लड़ाई और निगम के कारोबारी अधिकारों को हासिल करने की कशमकश के रूप में देखा जा रहा है।

असल में निगम चुनाव एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत शहर में सड़कें, पानी, सफ़ाई, पानी का निकास, पार्कों इत्यादि की व्यवस्था और इन सबका रख-रखाव करने के लिये सदस्यों को चुना जाता है ताकि करदाताओं के पैसे को उन्हीं पर ईमानदारी से लगाया जाये।

इसके ठीक उलट

चुनाव के नाम पर कुछ विख्यात अथवा कुख्यात ताकतों के बीच निगम के लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये के सालाना बजट को ख़ुर्दबुर्द करने के अधिकार की लड़ाई है।

जैसा कि सब जानते हैं कि देश की तकरीबन 95 फ़ीसदी जनता किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने का ख्वाब तक नहीं देख सकती। भ्रष्ट राज-नेताओं बाहुबलियों, दो नंबरी व्यापारियों और अंडरवर्ल्ड के मुखौटों ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल, महंगा, घिनौना और ख़ौफ़नाक बना दिया है कि आम नागरिक जो अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी से प्यार करता है, वह इस बदबूदार बीहड़ के करीब से गुजरना भी पसंद नहीं कर सकता।

क्या आप जानते हैं?

फरीदाबाद में कुछ मंत्री एवं बाहुबली ताकतें अपने चमचों को नगर-लूट का अधिकार दिलवाने कें लिए साम-दाम-दंड-भेद जैसे सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। शराब की छबीले, पांच सौ के नोटों की गड्डियां, जूते, डंडे, गोली की धौंस, इन प्रयासों के कुछ मशहूर नमूने हैं। इतने पर भी इन मंत्रियों का पेट नहीं भरता, क्योंकि इस सबके बावजूद गिनती के दिन यह सब लोग गणना अधिकारियों के सिरों पर बैठ कर एक-एक मिनट का हिसाब मांगते हैं और जरूरत पड़ने पर शोर-शराबे और धांधली के नाटकों की आड़ में दुबारा गिनती का ढोंग रचा कर हारे हुए चमचों को विजयी घोषित करवाने तक से नहीं चूकते।

क्या यह प्रजातंत्र का घोर अपमान नहीं है?

पचास-पचास लाख खर्च करने के, हर तरह की तिकड़म और अनैतिक हरबे इस्तेमाल करने के बाद नगर निगम में पहुंचने वाले तथाकथित नगर निगम सदस्य अपना मेयर तक चुनने का अधिकार नहीं रखते। पहले तो मंत्री महोदय इन्हें इनके घरों से उठा कर भारत भ्रमण करवाने या किसी अज्ञात फार्म हाउस में मौज-मस्ती करवाने के बहाने बंधुआ बना कर रखते हैं। इसी मौज-मस्ती के दौरान इन बेचारों को नोटों की लालच, ओहदों के वादे, उनकी जान के खतरे की ओट में धमकाने का अनूठा अंदाज और इस सबके बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने गये चमचे पर सर्वसम्मति से चुने जाने की मोहर।

क्या यह सब फरीदाबाद के निवासियों के मूल अधिकारों का हनन और उनके साथ एक घिनौना मजाक नहीं है?

मेयर की कुर्सी पर बैठने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति को चुना जाता है?

1. आला अफ़सरों और मंत्रियों के सामने आंख उठा कर बात न करे।
2. वह कोई सवाल न करे अथवा अच्छा हो उसे सवाल करना आता ही न हो।
3. ज्यादा महत्त्वाकांक्षी और ऊंची पसंद वाला न हो यानी संयमी जीव हो।
4. दफ़्तरी भाषा यानी अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर हो। अच्छा हो यदि बिल्कुल न हो।
5. हिंदी का ज्ञान भी केवल हस्ताक्षर करने या कामचलाऊ स्तर का हो ताकि प्रशासन सुचारू रूप से कार्य कर सके।
6. एक बत्ती वाली कार, एक सरकारी, बंगला, दो-चार टेलीफ़ोन और चार दर्जन सफ़ेद कुर्ते-पायजामे हासिल करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो।
7. पिछले जीवन में सीमित गतिविधियों के कारण गंभीर विवादों से बचा हो।
8. मंत्रियों और अधिकारियों को साष्टांग प्रणाम करने वाला सभ्य नागरिक हो तथा उनके पालतुओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो। समय आने पर या मांगे जाने पर बड़ी से बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहे।
10. दस नंबर (इसके बारे में कोई व्याख्या देना किसी समाचार पत्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।)

खैर समय के सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए नगर को कुछ नगर-पिता और एक सुशील मेयर मिल गया है। शहर की बीस लाख आबादी, बदहाल सड़कें, सूखे नल, नलों से रिसता बदबूदार पानी, खुले सीवर, गंदी नालियां, कूड़े के अंबार, आवारा पशु, बंदरों का आतंक, वीरान पार्क और अंधेरी गलियां, दोनों बाहें फैला कर इस नवप्रत्योपित मंडल का स्वागत करता है।

जनता बेचारी अत्याचारों की मारी, आप से और आपके आकाओं से उम्मीदें करने का दुस्साहस एक बार फिर कर रही है।

कुछ कीजिए वरना

हर शाख पर उल्लू बैठा है,
अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा।

- ज्योति संग

तख्ता-ए-नगर निगम

मेयर की कुर्सी का इतिहास गवाह है कि इसके लिए केवल एक उल्लू (लक्ष्मी जी का वाहन) या कोई अंधा, गूंगा और बहरा जीव ही उपयुक्त अधिकारी हो सकता है।

परन्तु

नवनिर्वाचित मेयर अशोक अरोड़ा के बारे में यह सब ग़लत साबित होने की संभावनायें हैं। अशोक अरोड़ा ने विजय ड्रामेटिक क्लब के प्रधान की हैसियत से लगातार लंबे अर्से तक निर्विवाद छवि को बहाल रखा और किसी भी लांछन या बदनामी की छींटों से अपने दामन को बचाने में कामयाब रहे।

अपने नये मेयर से शहर के बुद्धिजीवी यह आशा करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों और सियासी आकाओं के इशारों पर नाचने के बजाय अपनी छवि को बरकरार रखे। मेयर की कुर्सी आप के सफ़र की पहली सीढ़ी है। अपने पठानी खून, फरीदाबाद के नागरिकों का भरोसा और सच्चाई की हिफाजत के लिये ज़रूरत पड़ने पर इस कुर्सी को लात भी मारनी पड़ी तो जरा भी न हिचकिचायें। यदि ऐसा कर पाये तो शहर का बुद्धिजीवी वर्ग और लाखों लोग आप के साथ कंधे से कंधा मिला कर एक नये इंकलाब की शुरुआत करेंगे। याद रखें अब आप केवल अपने वार्ड के नहीं, सारे शहर, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं।

खून पठानों का है तू, अब उस की लाज बचा ले
उठ अशोक तू इंकलाब का, नारा आज लगा ले

अशोक अरोड़ा का मेयर बनना : सिर्फ हनुमान जी की भक्ति से क्या होगा?

फरीदाबाद नगर निगम के मेयर का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया। वार्ड नंबर 12 से चुने गये पार्षद अशोक अरोड़ा मेयर बने। अशोक अरोड़ा हनुमान-भक्त के रूप में जाने जाते हैं। पहले ये रामलीलाओं में हनुमान का रोल करते थे। मेयर बनते ही इन्होंने हनुमान जी का जयकारा लगाया और धर्मनगरी हरिद्वार चले गये। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे नगर का पूरा विकास करेंगे। उन्होंने मेयर बनाने के लिए मुख्यमंत्री हुड्डा के प्रति आभार भी जताया। यह तो पहले से ही तय था कि मेयर वही बनेगा जिसे मुख्यमंत्री चाहेंगे।

अशोक अरोड़ा के मेयर बनने से पंजाबी बिरादरी में काफी खुशी का माहौल है। इससे पता चलता है कि मेयर के चुनाव में बिरादरीवाद का खेल खेला गया है जिससे पंजाबी समुदाय खुश रहे।

अशोक अरोड़ा ने मेयर बनने के बाद कहा है कि वे शहर का पूरा विकास करवायेंगे। लेकिन वे कैसा और कितना विकास करेंगे, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। बहरहाल, नगर के प्रथम नागरिक का कहना है कि हनुमान जी की कृपा से वे जो और जैसा चाहेंगे, वही होगा।

अख़बारों में मेयर साहब के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा भी छापी गई है। कहा गया है कि अपने संघर्षपूर्ण दिनों में मेयर साहब ने रेहड़ी तक लगाई थी। इस तरह उन्होंने बड़ा ही कटु संघर्ष किया है और यही कारण है कि नगर के विकास के लिए वे कैसा भी संघर्ष करने को तैयार रहेंगे। अपने मेयर साहब की यह खासियत है कि पूर्व मेयर ब्रह्मवती खटाना की तरह वे भी अनपढ़ हैं। पर राजनीति की दुनिया में पढ़ा-लिखा होना कतई जरूरी नहीं समझा जाता। मेयर क्या, विधायक और सांसद तक अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ होने की वजह से वे कागज़ों पर तैयार की गई 'विकास' की योजनाओं को समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। इससे अफ़सरों को मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती है। वे योजनायें तैयार करते हैं और पार्षदों एवं मेयर की भूमिका महज उन पर अंगूठा लगाने तक सीमित हो जाती है। अब अपने मेयर साहब की भूमिका भी अंगूठा लगाने तक ही रहेगी।

> क्या विडंबना है कि एक कलर्क बनने के लिए डिग्रीधारी होना जरूरी है, पर जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे भी पढ़े-लिखे हों। जब तक व्यक्ति पढ़ा-लिखा न हो, उसमें जागरूकता का अभाव रहता है।

क्या विडंबना है कि एक क्लर्क बनने के लिए डिग्रीधारी होना जरूरी है, पर जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे भी पढ़े-लिखे हों। जब तक व्यक्ति पढ़ा-लिखा न हो, उसमें जागरूकता का अभाव रहता है। जागरूकता के अभाव में उसके लिए जनहित की समस्याओं को समझ पाना कठिन होता है। जब हमारे नेता अनपढ़ होंगे तो वे किस तरह विकास योजनाओं को कार्यान्वित करा पायेंगे? वे तो बस अंगूठा लगाने का ही काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के अनपढ़ होने से अफ़सरों की मौज होती है और वे जो चाहें, जैसा चाहें, करने को स्वतंत्र होते हैं। इस तरह देखा जाये तो अशोक अरोड़ा का मेयर बनना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, पर वे आम जनता के हित में काम करेंगे, यह एक प्रश्न है। सिर्फ हनुमान जी की भक्ति और रामलीला मंडली चलाने की पृष्ठभूमि शहर में क्या गुल खिलाएगी समय बताएगा।

- प्रतिनिधि

लोकतंत्र का काला सच

हरियाणा में अभी पंचायती चार स्तरीय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सरकारी विज्ञप्ति में कुछेक घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने की घोषणा की गई है। पूरे हरियाणा में अनेक खबरें आ चुकी हैं कि जहां भारी हिंसा हुई है। मेवात में तो कई जानें चली गई हैं। चुनावों के बाद सरपंच पद के हारे प्रत्याशियों द्वारा अनेक स्थानों पर झगड़ा करने की घटनाएं प्रकाशित हो रही हैं। इन घटनाओं को सवर्ण द्वारा दलितों पर अत्याचार भी बताया जा रहा है। लेकिन इसकी जड़ में कोई नहीं जा रहा है। पिछले दो दशकों से संसदीय चुनावों से लेकर विधानसभा के चुनावों में जो हथकंडे अपनाकर लुच्चे लफंगे सांसद, विधायकजन रहे हैं उसी तर्ज पर गांवों में भी गुंडे, बदमाश पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला पार्षद बन रहे हैं। कुछेक अपवाद हो सकते हैं लेकिन व कुछेक ही हैं।

संसदीय व विधानसभा के चुनावों की अपेक्षा पंचायती संस्थाओं के चुनावों की स्थिति अत्यंत भयावह है। गांवों में आपसी भाईचारा लगभग खत्म हो चुका है। यदि समय के साथ थोड़ा बहुत सुधरता है तो वह फिर पांच साल बाद फिर उसी ढर्रे पर आ जाता है। हर बार के चुनावों में निरंतर स्थिति खराब होती जा रही है। सरपंच पद के लिए प्रत्याशी 20-40 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। यह राशि गांवों की वोटर संख्या पर निर्भर करती है। गांवों में पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य व जिला पार्षद किसी पद का प्रत्याशी हो जो सबसे अधिक गुण्डा बदमाश होने के साथ सबसे अधिक शराब, सुल्फा, गांजा, मांस व नकद पैसे खर्च करेगा उसकी जीत निश्चित होती है। इस बार तो इन चुनावों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस रिकॉर्ड को तुड़वाने में सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग रहा है। मानों राजनेताओं ने कह दिया हो कि गांवों की जनता उन्हें तभी वोट देगी जब वह पूरी तरह बिकाऊ हो जाएगी।

इन चुनावों महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर जो महिलाएं चुनी गई हैं वह लोकतंत्र में बढ़ती महिलाओं की संख्या के आंकड़ों को तो साबित कर सकते हैं लेकिन वास्तव में वे केवल अपने-अपने शागिर्दों के मुखौटा मात्र है। मुखौटा भी ऐसा जिसका दीदार कोई नहीं कर सकता। जिले का उपायुक्त भी महिला प्रतिनिधियों वास्तविक किरदारों से ही काम चलाता है। जहां-जहां महिला प्रत्याशी होती हैं वहां भी सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वोटों को खरीदने का कार्य चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से आरंभ नहीं होता बल्कि चुनाव खत्म होने के बाद ही अगली योजना के लिए शुरू कर दिया जाता है। वोटर भी अपनी वोट की पूरी कीमत वसूलनी सीख गया है। आज गांव हो शहर हो सभी जगहों पर स्थानीय निकाय के चुनावों में वोटर अपनी हैसियत के हिसाब से कीमत वसूल रहा है। जहां संसदीय व विधानसभाओं में कुछ बड़े-बड़े ठेकेदार ही लाभ उठाते हैं। यहां आम वोटर अपनी कीमत वसूल लेता है। समझदार व विवेकशील मतदाता एकत्र नहीं होता है जिसका लाभ आज लोकतंत्र के नाम पर गुंडे बदमाश उठा रहे हैं। इन चुनावों में वोटरों को खरीदने के लिए अधिकांश प्रत्याशियों ने शराब, सुल्फा गांजा मांस के साथ-साथ शराब का भी प्रबंध किया था। शराब की पेटियां घर-घर पहुंचाई गई। जो लोग शराब नहीं पीते थे उनके लिए भोजन शीतल पेय व नकद पैसे का हिसाब था। घरों में महिलाओं के लिए शीतल पेय की व्यवस्था थी।